



GENERAL STUDIES (Test-18)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

GSM (M-I)-2418

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

Name: Karmveer Narwadia Mobile Number: _____
Medium (English/Hindi): Hindi Reg. Number: _____
Center & Date: MKN/ 21 Aug. 2024 UPSC Roll No. (If allotted): 0805596

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

There are TWENTY questions printed both in HINDI and ENGLISH.

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

केवल मूल्यांकनकर्ता द्वारा भरा जाए (To be filled by Evaluator only)

Question Number	Marks	Question Number	Marks
1.		11.	
2.		12.	
3.		13.	
4.		14.	
5.		15.	
6.		16.	
7.		17.	
8.		18.	
9.		19.	
10.		20.	
Grand Total (सकल योग)			

मूल्यांकनकर्ता (हस्ताक्षर)
Evaluator (Signature)

पुनरीक्षणकर्ता (हस्ताक्षर)
Reviewer (Signature)

www.drishtias.com

Contact: 8750187501



Feedback

- | | |
|---|--|
| 1. Context Proficiency (संदर्भ दक्षता) | 2. Introduction Proficiency (परिचय दक्षता) |
| 3. Content Proficiency (विषय-वस्तु दक्षता) | 4. Language/Flow (भाषा/प्रवाह) |
| 5. Conclusion Proficiency (निष्कर्ष दक्षता) | 6. Presentation Proficiency (प्रस्तुति दक्षता) |
-

1. संसदीय उत्तरदायित्व के स्तर को निर्धारित करने में विपक्षी दलों की भूमिका महत्वपूर्ण है। चर्चा कीजिये।

(150 शब्द) 10

The role of opposition parties is critical in determining the level of parliamentary accountability. Discuss.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

संविधान के अनुच्छेद 75 तथा 76
के अनुसार केन्द्र में संसदीय व्यवस्था
की गई है। संसद का उत्तरदायित्व है कि
वह सभी के सामाजिक-आर्थिक विकास को
बढ़ावा दे।

विपक्षी दलों की भूमिका

- ① विपक्षी दलों द्वारा सरकार से सवाल पूछे जाते हैं तथा सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है।
- ② विपक्षी दल सरकार की विफलता पर आलोचना करता है।
- ③ समसामयिक मुद्दों पर संसद में सवाल पूछने तथा विधिक कार्यवाही करने रूप में सरकार पर दबाव सृष्टि के रूप में कार्य करता है।

(iv) विपक्ष संसद के अंदर तथा बाहर सरकार की गतिविधियों पर मीडिया से रूबरू होती है।

(v) सरकार के द्वारा किए गए आर्थिक घोटाले पर सरकार से जवाब माँगा जाता है।

(vi) अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से लगातार सरकार में जनता के विश्वास की जाँच की जाती है।

(vii) ध्यानार्कषण, निंदा प्रस्तावों के माध्यम से सरकार का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है।

(viii) प्राइवेट मेम्बर बिल का उपयोग भी किया जाता है।

विपक्ष संसद में सरकार का उत्तरदायित्व निर्धारित करता है, यह सरकार की नीतियों में कमियों को प्रकाशित करके सुधार के लिए प्रेरित करता है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)

2. महिलाओं की श्रम बल भागीदारी को बढ़ाने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10
Discuss the role of Self-Help Groups in widening women's labour force participation. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)

समान सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग सामूहिक रूप से समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्व-नियंत्रित होते हैं स्वयं सहायता समूह कहलाते हैं।

PLFS सर्वे के अनुसार महिलाओं की श्रम बल भागीदारी लगभग 37% है, जिसमें 19% स्वनियोजित भूमिका में हैं। इस श्रम-बल भागीदारी में स्वयं सहायता समूह (SHG) की भागीदारी -

(i) महिलाओं को कौशल प्रदान किया जा सकता है।

Ex- राजस्थान में आजीविका

(ii) स्वनियोजन के लिए स्थल की उपलब्धता कराई जा सकती है।

Ex- बैंक सखी।

(iii) महिलाओं की निर्धनता को दूर करने उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य SHG द्वारा किया जाता है।

(iv) महिलाओं के लिए आर्थिक नियोजन के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

Ex- महिलाओं को सिलर मशीन दिलवाना।

(v) कॉशल विकास में वृद्धि कर रोजगार से जोड़ा जा सकता है।

(vi) महिलाओं के श्रम बल में वृद्धि करने के लिए सरकारी नीतियों पर जोर डाला जा सकता है।

पारदर्शिता में कमी।

हालांकि कुछ समस्याएँ भी हैं।

SHJ में प्रोफेशनलिज्म का अभाव।

SHJ में श्रृंखला का होना।

ज्यादातर SHJ शहरों में उन्नि

सामाजिक हटिवादी प्रथा।

इंदिरा गाँधी प्रियादर्शनी योजना, नाबार्ड का बैंक लिक्विड प्रोग्राम SHJ को महिलाओं के लिए आगे बढ़ाते हैं।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

3. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा मिलने से समाज के कल्याण के प्रति समग्र दृष्टिकोण को बल मिला है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10
- The approach to welfare is wholesome and whole-of-society, with increasing private sector participation through Corporate Social Responsibility(CSR). Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

केडबरी समिति के अनुसार एक कोरपोरेट को अधिकतम लाभ के साथ समाज तथा पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए कम्पनी अधिनियम में Corporate Social Responsibility के प्रावधान किए हैं।

C.S.R. सामान्त्या: कंपनी के पिछले वित्त वर्षों का कुल 2% प्रॉफिट लिया जाता है जो समाज की भलाई के लिए योगदान में लिया जाता है।

(1) C.S.R. में निजी क्षेत्र में भागीदारी से कम्पनियाँ सामाजिक पूँजी का विकास कर रही हैं।

Ex Reliance का बच्चों की शिक्षा पर विचार।

Dabur Hair oil का भी बच्चों की शिक्षा

(II) C.S.R. के चेंसों से स्वास्थ्य सेवा का विस्तार हुआ है।

Ex - Haldiram का बीकानेर में ईंसरयूनिट।

(III) C.S.R से पर्यावरणीय संघारणीयता को भाग बढ़ाया है।

Ex - JAIL Company ने हरित कार्य किया है।

(IV) C.S.R. गतिविधियों से जनजातिय क्षेत्रों के लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया है।

Ex - Amazon के प्रयास।

(V) समाज के सूत्री वंचितों तथा सुमेधियों को शासन में शामिल किया है।

C.S.R का चेंसा

स्वयं पर खर्च

पर्याप्त भांडित
नहीं होना

कुछ
कुर्तियाँ

C.S.R के रूप में
कम्पनी नकारात्मक
अतिरिक्त कर मानना

C.S.R के द्वारा कंपनी की छवि
मजबूत होती है, सामाजिक उत्थाण
होता है। अतः दोनों का परस्पर
लाभ होता है।

4. व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास के क्रम में मानसिक स्वास्थ्य, कम ध्यान दिये जाने वाला लेकिन प्रभावशाली चालक है। चर्चा कीजिये। इस संबंध में सरकार की सकारात्मक नीति क्या है? (150 शब्द) 10

Mental health is a less seen yet principally impactful driver of individual and national development. Discuss. What is the Government's positive policy momentum in this regard? (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

2017 में मानसिक स्वास्थ्य पर देखभाल की रिपोर्ट में पाया गया लगभग 1.7-3 मिलियन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य में देखभाल की आवश्यकता है-

doctor/patient
अनुपात काफी
कम होता

मानसिक स्वास्थ्य
पर कम ध्यान देना

समर्पित नीति
का निर्माण होना

केवल 10% से कम लोग ही

मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख पाते हैं

आत्महत्या की
लगातार बढ़ती
प्रवृत्ति

मानसिक स्वास्थ्य: प्रभावशाली चालक

- ① यह मनुष्य के जीवनकाल की उत्पादकता को प्रभावित करता है।
- ② लोगों के एक-दूसरे के रिश्तों में कड़वाहट का कारण बन जाता है।
- ③ आत्महत्या या यादश्च खो जाना जैसी हालात के शिकार हो जाते हैं।

(iv) लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का संबंध ही शारीरिक स्वास्थ्य तक होता है

(v) मानसिक स्वास्थ्य सफलता का निश्चरक होता है

(vi) व्यक्तिगत उन्नति के लिए आवश्यक

सकारात्मक प्रयास

(i) मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2007 का क्रियान्वन।

(ii) डिप्रेशन तथा मनोदुर्घटन जैसी पदहों को आगे बढ़ाया है।

(iii) मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

(iv) लोगों में जागरूकता फैलायी जा रही है।

मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देकर स्वस्थ मानव पूँजी का विकास कर सकते हैं जो संघातीय विकास के मजबूत होगी।

5. ग्रामीण भारत के शासन में सुधार हेतु शुरू की गई विभिन्न डिजिटलीकरण पहलों पर चर्चा कीजिये।

(150 शब्द) 10

Discuss the multiple digitization initiatives that have been unfolding in rural India to improve governance.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

ग्रामीण शासन प्रक्रिया में सूचना
तथा प्रौद्योगिकी (ICT) का प्रयोग उनके
डिजिटलीकरण पहल चलाई गई है
जिससे लोगों का सामाजिक-आर्थिक
विकास होता है -

विभिन्न पहल

① कृषि संबंधित →

कृषि दशनि, e-चौपाल, e-हाट,
e-NAM इत्यादि के माध्यम
से कृषि में बाजार उपलब्धता, विपणन,
भण्डारण, उत्पादन में सहयोग प्रदान किया
जाता है।

② स्वास्थ्य

किण, Telemedicine से जीवन
पहल स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार मिला है।

③ शिक्षा

स्वयं प्रभा जैसे चैनलों के माध्यम

से शिक्षा का विस्तार किया जाता है

(4) आपदा प्रबंधन →

INSAT, वृषि उपग्रह, चक्रवात early warning system, NDMA की संदेश प्रणाली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है

(5) भू-अधिकार के लिए स्वामित्व तथा Digital land Records modernization programmes

स्त्रीकरण का

निषेध

data

Safety &

समस्याएँ

नीति आयोग के अनुसार भू-अधिकार डिटल डिवाइस लगभग 40% के भास-पास

leakage स्थानीय भाषाओं की सुमावना में भुपलब्धता

two way Communication रही

डिजिटलीकरण को बढ़ावा देकर ग्रामीण भू-व्यवस्था का वैश्विक भू-व्यवस्था से जुड़ाव निर्धारित होगा।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

6. भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस लिखित संघीय संविधान को नम्यता (Flexibility) प्रदान करने का प्रयास किया गया है। विस्तारपूर्वक समझाइये। (150 शब्द) 10

A distinctive feature of the Indian Constitution is that it seeks to impart flexibility to a written federal Constitution. Elaborate. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

भारत का संविधान अमेरिका की तरह कठोर भी है तो ब्रिटेन की तरह लचीला भी। इसमें दोनों का संश्लेषण निहित है।

संविधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है जिसमें दोनों सदनों का विशेष बहुमत तथा कई बार राज्य विधायकों से पारित करवाया जाता है। यह कठोर संविधान दिखाया जाता है जिनमें निम्न हैं-

- ① मूल अधिकारों को कम करना।
- ② राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में परिवर्तन।
- ③ राज्य विधायिका की विधायी शक्तियों को कम करना।
- ④ विधायिका द्वारा सर्व सेवा सृजन करना।
अखिल भारतीय

वही कुछ जगह संविधान में नभ्यता
प्रदान की गई है जहाँ Art 368 से
बाहर संशोधन किए जाते हैं जिसमें
साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है

- (i) नए राज्यों का प्रवेश तथा गठन।
- (ii) संसद के विशेषाधिकार।
- (iii) संसद में कोटम।
- (iv) न्यायाधीशों की संख्या बढ़ना।

इस तरह कठोर तथा लचीली दोनों
व्यवस्था संघीय व्यवस्था को मजबूत बनाती
हैं।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

7. न्यायिक कार्यों की पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता एक सुदृढ़ एवं प्रभावी विधिक प्रणाली की आधारशिला है, जिससे लोक विश्वास सुनिश्चित और न्यायिक सिद्धांत का कार्यान्वयन संपुष्ट होता है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10
- The transparency and accountability of judicial function form the cornerstone of a robust and effective legal system, ensuring public trust and upholding the principles of justice. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

~~सुभाष~~ vs ~~काशी~~

इसी भी संगठन में पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता के विकास से संगठन में जनविश्वास सुनिश्चित होता है। इसी क्रम में मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय S.C. ने RTI के अन्दर लाया है।

न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता तथा
अवाधेद्विता की कमियाँ

- (i) कोलेजियम प्रणाली अपनाना।
- (ii) न्यायिक अवमानना के भन्तर्गत कार्रवाई।
- (iii) न्यायाधीशों के व्यवहार पर चर्चा नहीं।
- (iv) न्यायिक जवाबदेहिता से संबंधित कानून नहीं।
- (v) न्यायिक श्रृङ्खला सेटने के लिए कोई तैयारी नहीं।
- (vi) न्यायाधीशों को दायित्व मुक्ति का कार्य।

विधि। विधिक जवाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेहि। बनने के उपाय

- ① C.J.I. का कार्यालय RTI की धारा 2(h) में।
- ② 2002 → वेगलुरु में न्यायिक चार्टर सिद्धान्तों को भपनाना।
- ③ नरेश मिराजकर केस में लारव स्ट्रेमिंग को भागे लाना।
- ④ प्रक्रिया शपन - 2016 का प्रसौदा।
- ⑤ LIMBS, SOPACE जैसे E-gov. पहले का प्रयोग राना।

लोक विश्वास सुनिश्चित तथा न्यायिक सिद्धान्त

- ① जनता में जागरूकता में वृद्धि।
- ② लोगों के प्रति न्यायपालिका की जवाबदेही में वृद्धि।
- ③ अपराधिक न्याय जगती में सुधार।
- ④ भाई-भतीजावाद में गिरावट।

न्यायपालिका को स्वयं न्यायिक जवाबदेही तथा न्यायिक स्वतंत्रता में संतुलन लाना चाहिए।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

8. राज्यों की राजनीतिक कार्यप्रणाली के संबंध में राज्यपालों के गैर-पक्षपातपूर्ण बने रहने से संबंधित संवैधानिक अवधारणा गहन जाँच के दायरे में है। चर्चा कीजिये। (150 शब्द) 10

The constitutional conception of state governors occupying a non-partisan position with regard to the political functioning of states has come under severe strain. Discuss. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

राज्यों में अनुच्छेद 153 के तहत एक राज्यपाल होगा, जो केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा।

राजनीतिक कार्यप्रणाली में राज्यपाल की भूमिका

- ① राज्य कार्यपालिका के कार्य राज्यपाल के नाम पर होंगे।
- ② मंत्रिपरिषद् के परामर्श से राज्य की रिपोर्ट केन्द्र को सौंपेगा।
- ③ धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से पेश किए जाएंगे।
- ④ राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक भाराजित कर सकता है।
- ⑤ विधेयक को pocket veto की तरह प्रयोग कर सकता है।
- ⑥ मृत्युपंख के अलावा समादान शक्तियों का प्रयोग करता है।
- ⑦ विवेकाधीन शक्तियाँ भी मिलती हैं।

राज्यपाल की भूमिका से विवाद

- ① राज्यपाल केन्द्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं।
- ② राज्यपाल द्वारा अनिश्वास प्रस्ताव, विशेष सरकार में मनमानी की जाती है।
- ③ जान-बूझकर विधेयक को भारजित किया जाता है।
- ④ राजनीतिक पार्टियों से संबद्धता अधिक होती है।
- ⑤ राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश करना।

उपाय

- ① S.R. Bomai केस का पालन किया जाए।
- ② सरकारी तथा पूँछी आयोग की सिफारिशों का पालन किया जाए।
- ③ रामेश्वर उसाद वाद तथा नबाम रेबिया केस के निर्णयों को निर्धारित किया जाए।

राज्यपाल राज्य का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है, जसी है राज्यपाल तथा राष्ट्रपति दोनों मिलकर कार्य करते हैं।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

9. "कारागार सुधार न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि एक विधिक एवं सामाजिक आवश्यकता भी है।" इस कथन के आलोक में भारत में कारागारों की स्थिति का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (150 शब्द) 10
- "Prison reform is not just a moral imperative, but a legal and social necessity." In light of this statement, critically analyze the state of prisons in India. (150 words) 10

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)

भारत में पिछले राजस्व सूची का विषय है, जिससे कारागार सुधार में समस्या आती है।

कारागारों की स्थिति

- ① N. Judicial data grid के अनुसार जेलों की क्षमता से 130.2% की क्षमता से कार्य कर रही है।
 - ② जेलों में 78% ऊँची विचाराधीन है।
 - ③ महिला स्टाफ में केवल 13% हैं। जेलों में महिला कैदियों को समस्या आती है।
 - ④ लगातार हो रहे मानवाधिकार हनन के मामलों में वृद्धि। (NCRB रिपोर्ट)
 - ⑤ कारागारों में महिला कैदियों के यौन शोषण के मामले।
- कारागारों की स्थिति सुधार के लिए ज्ञात
- ① Model जेल नियमावली बनाना है।

- ② e- जेल से जेलों का मायुनिमीकरण किया है
- ③ fast track court का निर्माण किया है
- ④ faster app से जमानत में देरी।

जेलों से विधिक तथा सामाजिक
का सुधार आवश्यकता

① जेलों में AN मुन्ला समीति के अनुसार कैदियों पर नजर रखना तथा उन्हें मौशाल उदान करना।

② open jail system अपनाना।

③ न्यायिक सुधार को भागे बढ़ाना।

④ ~~करेंस~~ रेंडर्स → All India prison A.N. मुन्ला service का निर्माण किया जाए।

⑤ मानवाधिकार एजेंसियों का लगातार करें करना।

जेल सुधार से मानवाधिकारों को बल मिलता है तथा शासन में जनविश्वास पैदा होता है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

10.

भारत में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए इसके कार्यान्वयन संबंधी प्रमुख मुद्दों एवं चुनौतियों पर प्रकाश डालिये।

(150 शब्द) 10

Discuss the need for an All-India Judicial Service (AIJS) in India, highlighting key issues and challenges in its implementation.

(150 words) 10

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

99 वें संविधान संशोधन के माध्यम से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की आवश्यकता को बताया गया था।

आवश्यकता

- ① लगभग 5.5 cr मामले लम्बित हैं, उनके निपटारे के लिए।
- ② अवसरानुसार सुविधा तथा नियुक्ति में देरी को लेने के लिए।
- ③ सुलभ तथा कम खर्चीला न्याय उपलब्ध बनाना।
- ④ न्यायिक पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता में वृद्धि करना।
- ⑤ संविधान के अनुच्छेद 38(b) के अनुसार सभी को न्याय मिले।
- ⑥ खरिद न्याय एक मूल अधिकार है।

कायन्विन संबंधी मुद्दे एवं चुनौतियाँ

- ① जिला जजों की स्वायत्तता को खतरा।
- ② संघवाद की उणाती के विरुद्ध।
- ③ शक्ति के पृथक्करण सिद्धान्त का अन्वेषण।
- ④ Local आरण तथा महिला आरण को खतरा।
- ⑤ न्यायालयों में स्थानीय भाषा का प्रयोग से संबंधित समस्या।
- ⑥ लोगों के प्रति समवेशित नही।
- ⑦ न्यायालयों में अधीनस्थ ऊपरी सरेना से ज्यादा प्रभावित होना।

All India judicial Service एक नवाचार है जो लम्बित मामलों को देखते हुए आवश्यक है लेकिन न्यायिक स्वतंत्रता की सुरक्षा भी ध्यान में रखना चाहिए।

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

11.

सराहनीय प्रयासों के बावजूद, भारत की जनजातीय जनसंख्या तक स्वास्थ्य सेवाओं के सफल वितरण में विभिन्न चुनौतियाँ विद्यमान हैं। विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15

Despite commendable efforts, there are several obstacles that hinder the successful delivery of healthcare services to the tribal population of India. Analyse. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

भारत में 2011 की जनसंख्या के
अनुसार लगभग 8-8% जनसंख्या अनुसूचित
जनजाति की तिवस कती है। यह संख्या
स्वास्थ्य सुविधाओं से ग्रस्त है -

सराहनीय प्रयास

- ① आयुदमान भात योजना के माध्यम से पारिवारिक बीमा दिया है।
- ② इ-5 धनुष योजना, पोलियो मिशन के माध्यम से नवजातों का उपचार।
- ③ सभी आँगनवाड़ियों में मुफ्त टीका लगाया जाना।
- ④ आकांक्षी जिला कार्यक्रम के द्वारा स्वास्थ्य सेक्टर का ध्यान।
- ⑤ राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सफाई प्रयास।

जनजातीय सेवाओं के वितरण में विभिन्न
युर्नैतियाँ

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)

- ① जनजातियों का सम्पूर्ण डेटा अनुपलब्ध होता है साथ ही मुख्य धारा से उनका समावेश नहीं हो पाया है। यही कारण है रिलिफ़ प्रोग्राम 80% जनजातिय महिला एनीमिक है।
- ② सर्वाधिक रैसल, एड्स का बढ़ता खतरा भी उनकी स्वास्थ्य युर्नैतियों को दिखाता है जहाँ वे बिना कागजी राश्विही के एड्स के पीनीगत संक्रमण को ठोक नहीं पा रहे हैं।
- ③ जनजातिय जागसकता में कमी।
- ④ पोषक तत्वों का उपयोग न के बराबर किया जाता है।
- ⑤ साक्षरता दर काफी कम है।
- ⑥ Sickle cell एनीमिया रोग का भी M.P में जनजातियों में फैला है जिसका डायग्नोसिस नहीं किया जा रहा है।
- ⑦ जनजातिय अंगों में हॉस्पिटल तथा

अवसंरचना की भुपलक्ष्यता।

(VIII) ग्रामीण तथा जनजाति स्वस्थता में
उन्नत diagnostic label का न होना।

क्या किया जाए?

- ① जनजाति की क्षेत्र आधारित नीतियों को लागू किया जाए।
- ② भाग्यमान कार्ड के साथ-साथ digital Health id card के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाए।
- ③ भौगोलिक, आशा सहयोगिता तथा उच्चगुणी पुलिसिंग के सहयोग से जागरूकता बढ़ाई जाए।
- ④ पोषक तत्वों का खाद्य में बढ़ाना चाहिए।
- ⑤ diagnostic, Infra में विकास किया जाना चाहिए।

जनजाति स्वास्थ्य को मजबूत करके लगभग 10% जनसंख्या को सामाजिक पूँजी में बदला जा सकता है जो आर्थिक संकट में योगदान देगा।

12. विधायी अंग के रूप में संसदीय कार्यों की गणना कीजिये। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संसदीय संस्था और उसकी प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाने हेतु सुधार एवं तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई अनिवार्य है? (250 शब्द) 15
Enumerate the functions of Parliament as the legislative organ. Do you agree that reforms and urgent remedial action seem imperative for making parliamentary institutions and processes effective?

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)



उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

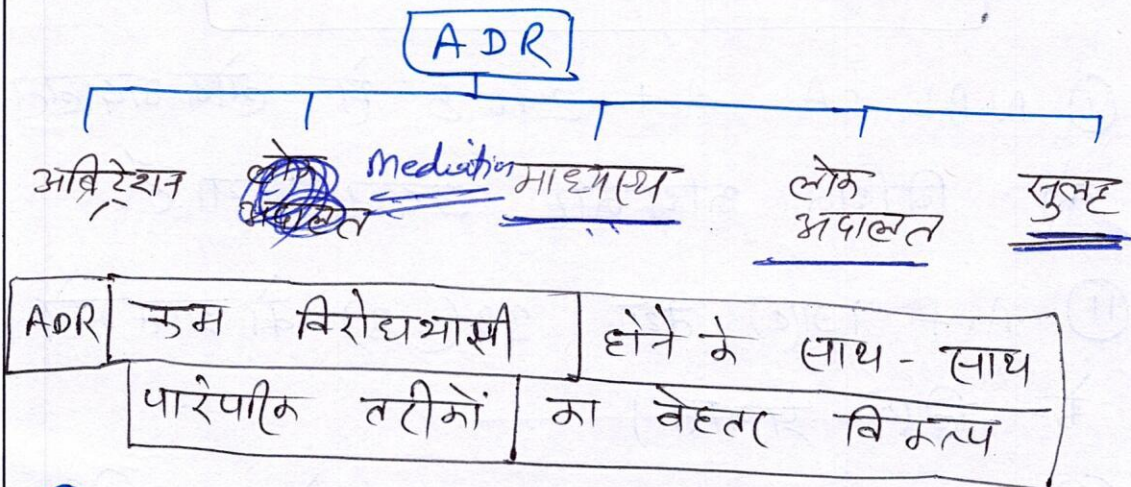
13. वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र कम विरोधाभासी होने के साथ विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान कर सकते हैं। चर्चा कीजिये। इस दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं? (250 शब्द) 15

Alternate Dispute Resolution mechanisms are less adversarial and can provide a better substitute to the conventional methods of resolving disputes. Discuss. What are the government's efforts to bring out a transformative shift towards it? (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।

(Candidate must
not write on this
margin)

न्यायपालिका के बाहर सभी प्रकार
के विवादों जैसे- व्यवसायिक, व्यक्तिगत का
निपटारा किया जाता है, ADR कहलाता है।



- ① ADR कम समय में, कम खर्चों पर न्याय उपलब्ध कराता है।
- ② न्यायाधीशों से पारंपरिक के विपरीत सीधे बात की जा सकती है।
- ③ न्यायपालिका के बाहर दोनों पक्षों में जागरूकता तथा उनके अधिकारों पर बल दिया जाता है।

- ④ न्यायपालिका के कोस में रुकी ।
- ⑤ न्यायपालिका की वदनीय जगह ।
- ⑥ असहमत होने पर कार्टवर्क बीच में ही वापिस ली जा सकती है।

ADR की दिशा में प्रयास

- ① NAL SA Act 2008 से लोक न्याय को विधिक अधिकार उदान किया है।
- ② Art 19(c) तथा 38(B) को जल्द करने के लिए प्रयास ।
- ③ माहसूय तथा सुलह संशोधन अधिनियम का क्रियान्वन ।
- ④ सिंगापुर सेटलमेंट का भारत दस्तावेज ।
- ⑤ छत्तीसगढ़ ने e- लोक न्याय को अपनाया है।
- ⑥ माहसूय अधिनियम 2023 को पारित किया गया है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

(VII) Arbitration Council का संस्थागत रूप पर बल दिया गया है

(VII) जनजागृकता बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं

सरकार को लम्बित मामलों को निपटाने के लिए न्यायिक सुधार की आवश्यकता है।
ADR के अनुपालन से त्वरित सुनवाई के अधिकार की सुरक्षा हो सकती है।

उम्मीदवार को इस
मार्ग में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

14.

दिल्ली के शासन और भारत के संघीय ढाँचे पर इसके संभावित प्रभाव पर विचार करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (GNCTD) (संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

(250 शब्द) 15

Critically examine the provisions of the Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) (Amendment) Act, 2023 considering its potential impact on the governance of Delhi and the federal structure of India.

(250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।

(Candidate must not write on this margin)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 AA के माध्यम से दिल्ली के शासन को चलाया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली के शासन को प्रभावी बनाने के लिए GNCTD संशोधन अधिनियम लाया गया।

GNCTD Act के प्रावधान

① NCCSA की स्थापना

सिविल सेवाओं की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है।

② दिल्ली के वैधानिक आयोगों, ट्रिब्यूनल में, बोर्ड, आयोग में नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, मतभेद होने की स्थिति में (अप्यपाल रिजर्विंग होगा)

→ विभागों के सचिवों को संबंधित मंत्री से परामर्श किए बिना उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव के मामले को उठा सकता है।

→ दिल्ली सत्कार द्वारा बनाए निर्णयों के लिए उपराज्यपाल सिफारिश सेगा।

आलोचना

- ① यह चुनी गई सर्वेधानि सत्कार का उत्प्रेषण करता है। यह
- ② लोकतंत्रिक प्रतिक्रियाओं का उत्प्रेषण करता है।
- ③ दिल्ली सत्कार की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है।
- ④ उपराज्यपाल दिल्ली की सत्कार का मतलब होता दिख रहा है।
- ⑤ S.C. के कसले जिसमें भूमि, पुलिस,

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

सार्वजनिक व्यवस्था केन्द्र सरकार सरकार के पास होगी, अन्य शक्तियाँ दिल्ली सरकार के पास होगी का उल्लेख।

- दिल्ली विधानसभा का उत्तरदायित्व नहीं
- विधानसभा सिर्फ राय देने के लिए।

आगे की राह

- ① उपराज्यपाल तथा दिल्ली सरकार के मध्य संवादों को आगे बढ़ाना चाहिए
- ② अधिनियम की हर 5 साल में विशेष समीति द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए
- ③ दिल्ली के लोगों की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए

UNCT & Act दिल्ली सरकार के प्रभाव को कम करता है, वहीं उप-राज्यपाल को मजबूत करता है।

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

15. भारतीय लोकसभा और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में अध्यक्ष की भूमिका की तुलना कीजिये। चर्चा कीजिये कि ये भूमिकाएँ अपने-अपने विधायी निकायों की कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावित करती हैं। (250 शब्द) 15
- उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)
- Compare and contrast the role of speaker in the Indian Lok Sabha and British House of Commons .
Discuss how these roles impact the functioning of their respective legislative bodies. (250 words) 15



उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

16. राजकोषीय संघवाद सुनिश्चित करने एवं केंद्र और राज्य सरकारों की राजकोषीय शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने में वित्त आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (250 शब्द) 15
- Critically evaluate Finance Commission's crucial role in ensuring fiscal federalism and maintaining a balance between the fiscal powers of the central and state governments. (250 words) 15
- उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)



उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

17. क्या भारत ने अपनी वैश्विक स्थिति और प्रभाव को बढ़ाने के लिये अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठाया है? विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द) 15
- Has India leveraged its soft power to enhance its global stature and influence? Analyze. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



18. अपनी स्थापना के बाद से पिछले दो दशकों से अधिक समय में, बिम्स्टेक (BIMSTEC) ने अपनी विशाल क्षमता का उपयोग करते हुए सामूहिक उन्नति की दृष्टि वाले समूह के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने में एक लंबा सफर तय किया है। टिप्पणी कीजिये। (250 शब्द) 15
- In the past more than two decades since its establishment, BIMSTEC has come a long way in distinguishing itself as a group with a vision for collective advancement utilizing its vast potential. Comment. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस हाशिये में नहीं लिखना चाहिये।
(Candidate must not write on this margin)



उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

19. | उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते वैश्विक ऋण संकट के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रमुख परिणामों का परीक्षण कीजिये। (250 शब्द) 15
- Examine the major outcomes of soaring global debt crisis in emerging and developing economies on international relations. (250 words) 15
- उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



20. यूरोप का हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर बढ़ता ध्यान तथा भारत के साथ गहराता आर्थिक और तकनीकी सहयोग परस्पर लाभ प्रदान करता है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द) 15
- Europe's increased focus on the Indo-Pacific and the deepening economic and technological collaboration with India offer mutual benefits. Discuss. (250 words) 15

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)

उम्मीदवार को इस
हाशिये में नहीं
लिखना चाहिये।
(Candidate must
not write on this
margin)



Space for Rough Work
(रफ़ कार्य के लिये स्थान)



Space for Rough Work
(रफ कार्य के लिये स्थान)



Space for Rough Work
(रफ़ कार्य के लिये स्थान)



Space for Rough Work
(रफ कार्य के लिये स्थान)